

Regarding corruption in Integrated Child Development Scheme (ICDS) in Punjab including substandard food, low wages, etc.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) : मैडम, मैं इस सदन के और डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री के ध्यान में लाना चाहूंगी कि पंजाब के आईसीडीएस प्रोग्राम में बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आंगनवाड़ियों में प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स और 0 टू 6 ईयर्स के बच्चों को दिया जाता है। सेंटर ने 150 रुपये का जो बजट दिया, फेक बेनिफिशियरीज़ दिखा करके, उसे 300 करोड़ रुपये का बजट करके जो खाना है, वह आईसीडीएस रूल्स के हिसाब से प्राइवेट आधारों को नहीं दिया जा सकता। इसे स्टेट ओन्ड बॉडीज मार्कफेड और वेरका बनाते थे, लेकिन सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाकर प्राइवेट आधारों को 300 करोड़ का सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का काम दे दिया गया है, जहां सबस्टैंडर्ड खाना देकर बच्चों और मदर्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां टोटल फ्लायटिंग ऑफ रूल्स हो रहा है। इसके बारे में मैंने मंत्री जी को लिखकर भी दिया है। आज मैं डिमांड करती हूँ कि सीबीआई की एक इंक्वायरी की जाए। यह नहीं हो कि केंद्र पैसे रोक दे, क्योंकि गरीब बच्चियों और मांओं का इसमें क्या दोष है? इसमें वहां की सरकार घपला कर रही है। आपको हैरानी होगी कि जो 28 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो महज 4,500 रुपये महीने में काम करती हैं, उनके हेल्पर्स को 2,200 रुपये महीने के मिलते हैं, जो मिनिमम वेजेज़ से भी कम हैं। इनको जहां सरकार को रेग्युलराइज करना चाहिए, वह तो क्या किया, लेकिन जब ऑल इंडिया आंगनवाड़ी की प्रधान ने खराब, पॉइजनस खाने का मुद्दा उठाया, तो उनको डिसमिस कर दिया। सरकारी अफसर सीडीपीओ को सस्पेंड कर दिया है और सरे आम लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन रूल्स के अगेंस्ट खास लोगों को किकबैक करने के लिए, करप्शन करने के लिए दिया जा रहा है। मैं डिमांड करती हूँ कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करके वहां की सरकार और मंत्रियों को पीनलाइज किया जाए। वहां के लोगों का खाना और स्कीम का पैसा न रोका जाए। जैसा कि नेशनल हेल्थ मिशन में भी किया है, आरडीएफ में किया है, शिक्षा में भी किया है। पंजाब के लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां की सरकार घपले कर रही है। आम आदमी की सरकार घपलों की सरकार है। यह सारा देश जानता है।